THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) and (b) Modernisation, adoption of new technology and quality control for the purposes of producing processed food products acceptable and competitive in the international market will help in increase of exports. Government have libralised Industrial Policy allowing automatic approval for technology agreements, automatic approval for foreign collaboration upto 51 percent equity for manufacture of wide ranging food products; have provided fiscal incentives such as reduction in customs/excise duties on food processing machineries and components. Government is also implementing various plan schemes for research and development, quality control and for development of suitable machineries.

कोंकण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

4146. डा. बापू काजदाने :
श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजि उद्यमियों (अनिवासी भारतीयों आदि ने कोंकण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने के लिए अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) जी हां । मैं० फूड कान्सेप्ट इंडिया लि. का अनिवासी भारतीय पूंजी-निवेश की भागीदारी से थाने, महाराष्ट्र में एक खजिन जल यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसी तरह मैं० कैडबरी इंडिया का मै. कैडबरी स्विप्स ब्रिटेन की इक्विटी भागीदारी के साथ थाने, महाराष्ट्र में चाकलेट बनाने के लिए अपने यूनिट के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है । इन दोनों प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई है ।

Investment in Food Processing Industries

4147. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Food Processing Industries attracted a huge investment commitment within a short span following the Government's thrust on exports of agro-based products;

(b) if so, what are the details of the commitments;

(c) whether Government have cleared proposal of the foreign investment in the food processing sector; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (d) Yes, Sir. Since the liberalisation of the Industrial Policy in July, 1991, about 1,993 Industrial enterpreneurs memoranda have been filed in respect of Food Processing Industries involving an investment of about Rs. 25,343 crores upto February, 1993. Government have also approved investment proposals of over Rs. 4000 crores in the food processing and deep fishing sector. These include proposals of joint ventures, export-oriented units,

units requiring Industrial Licences units with Non-Residents (NRIs) and Overseas Corporate Bodies (OCBs) investments and the units for which plan assistance has been provided. These proposals envisage foreign equity investment of approximately Rs. 780 crores.

Revival of Deep Sea fishing industry at Visakhapatnam

4148. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD PROCESSNG INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have shelved various proposals to create a congenial environment for revival of the deep sea fishing industry based in Visakhapatnam;

(b) whether it is a port of liberalised policy to let Indian deep sea fishing industry to either away; and

(c) if not, reasons for shelving fresh rehabilitation package of relief of such deep sea fishing units based in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में आलू का प्रसंस्करण

44149. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन में हो रही निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा इसके प्रसंस्करण की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता, फिर भी इस मंत्रालय ने आलू पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों सहित ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए सरकारी सेक्टर/संयुक्त सैक्टर के उपक्रमों, सरकारी सैक्टर के संगठनों आदि को वित्तीय सहायता देने के लिए अनेक योजना-स्कीमें, तैयार की हैं । परंतु उत्तर प्रदेश से उस राज्य में आलू पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता मांगने का कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार

4150. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार के संबंध में सरकार की क्या योजना है ;

(ख) इस प्रयोनार्थ कितने रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान ऐसे कितने उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों के लिए योजना आयोग द्वारा 146 करोड रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है । वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना के लिए मंजूर किया गया परिव्यय 40 करोड रुपए था परंतु 1993-94 के लिए 45 करोड रुपए का परिव्यय रखा गया है । खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन बुनियादी सुविधाओं, अनुसंधान एवं विकास, अध्ययन एवं सम्भाव्यता रिपोर्टों, विपणन आदि के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों/संगठनों आदि को वित्तीय सहायता देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनेक विकासात्मक/योजना स्कीमें तैयार की गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता ।